



कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिये उच्चस्तरीय समिति

चर्चा में क्यों?

05 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिये उच्चस्तरीय समिति (Committee to Examine the Demands of Employees and Officers) के गठन को मंजूरी दी।

प्रमुख बंदि

- यह समिति वेतन वसिंगति, वेतन सुधार, पदोन्नतिके अवसरों, एसीपी, भत्तों की नरितरता एवं उपयोगिता, योग्यता, दायित्वों, वृत्तीय भार इत्यादिके परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों, यथा- पटवारी, मंत्रालयिकि एवं कॉन्स्टेबल आदिकि मांगों का अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण एवं परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसा करेगी।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानवृत्त अधिकारी खेमराज चौधरी इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा सेवानवृत्त आईएएस अधिकारी वनिद पांड्या समितिके सदस्य एवं संयुक्त सचवि, वृत्त (नयिम) सदस्य सचवि होंगे।
- उल्लेखनीय है कि वृत्त एवं वनियोग वधियक 2021-22 पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने कर्मचारी-अधिकारी संगठनों की मांगों के संबंध में उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की थी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/committee-to-examine-the-demands-of-employees-and-officers>